

चुनौतियों से गुजरते हुए: वित्तीय स्थिरता और भारत*

श्री शक्तिकान्त दास

मैं सीएनबीसी टीवी18 की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित ग्लोबल लीडरशिप शिखर सम्मेलन में आकर बहुत खुश हूँ। मैं सीएनबीसी टीवी18 की टीम को उसके वर्षों से सफल सफर के लिए बधाई देता हूँ। भारतीय रिज़र्व बैंक के तीन प्रतिष्ठित पूर्व गवर्नरों - डॉ. सी. रंगराजन, डॉ. बिमल जालान और डॉ. वाई.वी. रेड्डी को सम्मानित करने के इस अवसर पर शामिल होना मेरे लिए वास्तव में सम्मान की बात है। आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के नीति निर्माण में अपने असाधारण प्रदर्शन के साथ वे केंद्रीय बैंकिंग की कला और विज्ञान में अग्रणी स्थान रखते हैं। एक पूर्ण-सेवा केंद्रीय बैंक के संरक्षक के रूप में उन्होंने मौद्रिक ढांचे के अलावा देश की वित्तीय, विनिमय दर और बाह्य क्षेत्र की नीतियों में मौलिक बदलाव शुरू किए। मैं आज भारतीय रिज़र्व बैंक को आकार देने में डॉ. रंगराजन, डॉ. जालान और डॉ. रेड्डी द्वारा निर्मित समृद्ध परंपरा और विरासत को नमन करता हूँ। उनके योगदान से प्रेरणा लेते हुए मैं आज 'चुनौतियों से गुजरते हुए: वित्तीय स्थिरता और भारत' विषय पर बात करूंगा।

हाल के वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था निरंतर और नए-नए आघातों के दौर से गुजर रही है। यह "अति अस्थिरता"¹ (ग्रेट वॉलेटिलिटी) का दौर था, जो "ग्रेट मॉडरेशन" के पिछले दौर से अलग था।² वैश्विक महामारी, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, युद्ध, भू-राजनीतिक संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के जटिल और विविध आघातों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। ये पाठ्यपुस्तकों में बताए गए सामान्य आघात नहीं थे या इनके लिए कोई मानक नीतिगत प्रतिक्रियाएँ नहीं थीं। इसलिए, इस अस्थिरता की अवधि से पार पाना भारत सहित हर देश के लिए एक कठिन चुनौती थी।

* K14 नवंबर 2024 को सीएनबीसीटीवी18 ग्लोबल लीडरशिप शिखर सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का मुख्य भाषण।

¹ गवर्नर का वक्तव्य: 8 दिसंबर 2023।

² 'ग्रेट मॉडरेशन' 1980, 1990 और 2000 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक आर्थिक अस्थिरता में आई कमी की अवधि को दिया गया नाम है।

वर्तमान वैश्विक संदर्भ

महामारी के बाद विस्तारवादी नीतियों को लगभग सभी जगह एक साथ अपनाने के बाद दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और यूक्रेन युद्ध के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण समान रूप से एक साथ मौद्रिक नीति को सख्त करने के कदम उठाए। कुल मिलाकर इस नीति ने दुनिया भर में अच्छा काम किया।³ मंदी रहित मौद्रिक सख्ती (सॉफ्ट लैंडिंग) सुनिश्चित की गई है, लेकिन मुद्रास्फीति के लौटने और संवृद्धि के धीमा होने का जोखिम बना हुआ है। भू-राजनीतिक संघर्ष, भू-आर्थिक विखंडन, पण्य कीमतों में उतार-चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन से होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियाँ लगातार बनी हुई हैं।

इस पूरी अवधि में कीमतों और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना मुश्किल काम रहा है जैसा कि 2023 में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग क्षेत्र में हुई उथल-पुथल से दिखाई देता है। चुनौती हमेशा एक ओर कार्रवाई बहुत कम या बहुत देरी से करने और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी करने के बीच होती है। मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों और वित्तीय क्षेत्र में विकास के साथ-साथ उभरती स्थिति के बीच के अंतर को सही ढंग से समझना और निर्णयों को समय पर लेना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। केंद्रीय बैंकों ने इस बार कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया है।

इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में, मैं वैश्विक स्तर पर कुछ विरोधाभासों को उजागर करना चाहता हूँ जिन्हें हम इस समय देख रहे हैं। सबसे पहले, सरकारी बॉण्ड का प्रतिफल बढ़ रहा है, जबकि कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ दरों में कटौती के माध्यम से नरमी का मार्ग अपना रही हैं, जो इस तथ्य को रेखांकित करता है कि ट्रेजरी बाज़ार वैश्विक और घरेलू, कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जो केवल नीति समायोजन से कहीं अधिक हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी डॉलर भी मज़बूत हो रहा है, जबकि फेड दरों में कटौती कर रहा है। दूसरा, मज़बूत अमेरिकी डॉलर और उच्च बॉण्ड प्रतिफल से अप्रभावित, सोने और तेल की कीमतें – ऐसी दो वस्तुएँ जिनका मूल्य आम तौर पर एक साथ घटता-बढ़ता है – भारी अंतर दिखा रही हैं। तीसरा, बढ़ते भू-राजनीतिक

³ अध्याय 2, वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ, अक्टूबर 2024।

जोखिमों और वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता के बीच एक दिलचस्प विरोधाभास भी उभर रहा है। जबकि हाल के वर्षों में भू-राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं, वित्तीय बाज़ारों ने बढ़ती अनिश्चितताओं के होते हुए भी काफी समुत्थानशीलता दिखाई है। चौथा, प्रतिबंधों, शुल्कों, आयात शुल्कों, बढ़ते सीमा-पार प्रतिबंधों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बावजूद वैश्विक व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है। पांचवां, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने मौजूदा दौर में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) की तुलना में अधिक समुत्थानशीलता दिखाई है।

भारतीय संदर्भ

इन प्रतिकूल परिस्थितियों और विरोधाभासों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक बुनियादी ढांचे, स्थिर वित्तीय प्रणाली और समुत्थानशील बाह्य क्षेत्र जैसे बफर द्वारा संचालित होकर सुचारु रूप से आगे बढ़ रही है। हमारा प्रयास विवेकपूर्ण और सक्रिय नीतिगत दृष्टिकोण को अपना कर अपने मूल ढांचों को अधिक मजबूत करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना रहा है। हमारा मुख्य ध्यान वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर रहा है, जो संवृद्धि और समृद्धि का मार्ग है।

2019 में, हमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र में गंभीर दबाव का सामना करना पड़ा। चलनिधि संकुचित हो गई थी और वित्तीय बाजारों में विश्वास की कमी थी। हाल के वर्षों में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग, दोनों क्षेत्रों में बैंक दबाव की कुछ घटनाएं घटी थीं। इन सभी आपातकालीन स्थितियों में रिजर्व बैंक ने संकट के विस्तार को रोकने और बाजारों में स्थिरता और विश्वास बहाल करने के लिए प्रभावी उपाय किए। इसके साथ-साथ, हमने अपनी विनियामक संरचना और पर्यवेक्षी निगरानी को मजबूत किया ताकि कमज़ोरियों की पहचान की जा सके और भविष्य के लिए तैयार रहा जा सके। इसलिए, इस अवधि के दौरान हमारे अनुभव का विश्लेषण करना उचित है, न केवल एक सफलता की कहानी के रूप में - बल्कि, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य के लिए सबक के रूप में।

⁴ ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स, डब्ल्यूटीओ, अक्टूबर 2024 के अनुसार विश्व माल व्यापार की मात्रा 2024 में 2.7 प्रतिशत और 2025 में 3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि 2024 और 2025 में विश्व व्यापार की मात्रा क्रमशः 3.1 और 3.4 प्रतिशत बढ़ेगी (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2024)।

जब कोविड-19 महामारी ने हमें प्रभावित किया, तो हमारी प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक थी। हमने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही कारोबार निरंतरता के उपाय लागू कर दिए थे। हमने वित्तीय बाजार संचालन और भुगतान प्रणालियों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 200 अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं के साथ एक विशेष संगरोध केंद्र (क्वार्टीन केंद्र) स्थापित किया। सभी विनियमित संस्थाओं को व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने और अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए तत्काल आकस्मिक उपाय करने की सलाह दी गई।

मौद्रिक नीति और चलनिधि संचालन

मौद्रिक नीति ने पिछले छह वर्षों में एक पूर्ण चक्र पूरा कर लिया है - 2019-22 के दौरान एक सहजता चक्र और उसके बाद समान स्तर का एक सख्त चक्र। हमने तत्समय की स्थितियों और परिदृश्य के अनुसार संवृद्धि अथवा मुद्रास्फीति, को प्राथमिकता देने के लिए लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) में निहित लचीलेपन को अपनाया। उदाहरण के लिए, जब कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधि गंभीर दबाव में आ गई, तो हमने मुद्रास्फीति के बजाय संवृद्धि को प्राथमिकता दी और नीति दरों में कटौती की और प्रणाली में भारी मात्रा में चलनिधि उपलब्ध कराई। ये उपाय भविष्य में उत्पन्न होने वाली कीमत और वित्तीय स्थिरता चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए काफी नपे-तुले थे। इसके अलावा, सहजता चरण के दौरान अग्रगामी मार्गदर्शन (फॉरवर्ड गाइडेंस) मौद्रिक नीति और चलनिधि उपायों के लिए सहायक और पोषक सिद्ध हुआ। इसी के साथ-साथ, ऋणों के पुनर्भुगतान पर स्थगन और दबावग्रस्त ऋणों के लिए समाधान ढांचे सहित उचित विनियामक उपायों की भी घोषणा की गई।

बाद में, जब रूस-यूक्रेन युद्ध ने प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति में भारी व्यवधान पैदा किया और मुद्रास्फीति के नियंत्रण से बाहर होने का खतरा पैदा किया, तो हमने अपना ध्यान संवृद्धि से हटाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर केंद्रित कर दिया। हमने अपनी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों को आरंभ में ही लागू कर दिया और अपने रुख को बदलकर समायोजन वापस ले लिया। हम अपने चलनिधि प्रबंधन कार्यों में चुस्त और सक्रिय बने रहे। इसके

अलावा राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय की बात करें तो रिज़र्व बैंक की दरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति पक्ष उपायों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने में मदद की।

हाल की अवधि की बात करें तो, 7-9 अक्टूबर 2024 को अपनी बैठक में एमपीसी ने मौजूदा और अपेक्षित मुद्रास्फीति-संवृद्धि परस्पर गतिशीलता को ध्यान में लेते हुए मौद्रिक नीति के रुख को समायोजन को वापस लेने से बदलकर 'तटस्थ' करने का फैसला किया। एमपीसी ने संवृद्धि का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को टिकाऊ रूप से लक्ष्य के पास लाने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया। रुख में बदलाव से उभरती परिस्थितियों और दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक लचीलापन और विकल्प मिलता है।

कुल मिलाकर, 2021-24 के दौरान औसत संवृद्धि 8.0 प्रतिशत से अधिक रही तथा 2023-24 और 2024-25 (सितंबर तक) में हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होकर सहनीय सीमा के भीतर रही जो रिज़र्व बैंक की नीतियों की सफलता का प्रमाण है। यह भी उतना ही उल्लेखनीय है कि इन सभी कार्रवाइयों के बावजूद वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। हमारी दरों में बढ़ोतरी से पहले या उसके साथ विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का पालन किया गया था, जिसमें बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को रखने में अधिक छूट दी गई थी जिससे बाजार-चिह्नित नुकसान न्यूनतम हुआ। यह स्पष्ट है कि महामारी और मुद्रास्फीति में उछाल, दोनों के लिए हमारी कार्रवाई का स्वरूप निर्धारित करते समय हमारी नीतियां चुस्त, लचीली और संतुलित थीं। हम "संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता" के अपने अधिदेश के अनुरूप बने रहे। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के अंतर्निहित अधिदेश का भी पालन किया गया।

केंद्रीय बैंक संचार

इस पूरी अवधि के दौरान हमारी नीतिगत कार्रवाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए संचार एक महत्वपूर्ण साधन बना। महामारी के दौरान हमारा प्रयास व्यापक अर्थव्यवस्था, वित्तीय

बाजारों और आम जनता को विश्वास दिलाना था। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में 17 अप्रैल 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य में मैंने कहा था "हालांकि सामाजिक दूरी हमें अलग करती है, हम एकजुट और दृढ़ हैं। आखिरकार, हम उबरेंगे; और हम टिके रहेंगे"। हमने महात्मा गांधी के उद्धरणों का उपयोग करना शुरू किया जैसे "...मृत्यु के बीच जीवन कायम है...अंधकार के बीच प्रकाश कायम है" (17 अप्रैल 2020); "जब क्षितिज सबसे अंधकारमय होता है और मानवीय तर्क धराशायी हो जाता है, तब विश्वास सबसे प्रकाशमान होता है और हमारी सहायता के लिए आता है" (22 मई 2020)। इसी तरह के और भी कथन थे।

विशेष रूप से मैं 16 नवंबर 2023 को किए गए मैक्रो प्रूडेंशियल उपायों के बाद अपने दिसंबर 2023 के बयान का उल्लेख करना चाहूंगा: "वित्तीय स्थिरता एक सार्वजनिक लाभ है...हम संकट का इंतजार करके बाद में कार्रवाई करते नहीं करते हैं। विवेक ही हर समय हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है।" इन कथनों के पीछे की भावना संकटों की अवधि को झेलने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे संचार को उचित नीतिगत कार्रवाइयों का समर्थन प्राप्त था। जाहिर है, हाल के दिनों के अस्थिर समय में स्थिरता बनाए रखने में संचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्थिरता के लिए मजबूत विनियमन और पर्यवेक्षण

यह स्पष्ट है कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विनियमित संस्थाओं (आरई) के संबंध में एक मजबूत विनियामक ढांचा और एक मजबूत पर्यवेक्षी और निगरानी तंत्र महत्वपूर्ण है। जहां तक रिज़र्व बैंक का संबंध है, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर संशोधित मानदंड; एनबीएफसी के लिए पैमाना आधारित विनियमन; माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए संशोधित विनियमन; शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए चार-स्तरीय विनियामक दृष्टिकोण; और असुरक्षित ऋणों में संभावित ऋण आधिक्य को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम हैं जो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के हित में विनियमन के विवेकपूर्ण स्वरूप के कुछ उदाहरण हैं।

⁵ वित्तीय स्थिरता को नानी पालकीवाला मेमोरियल व्याख्यान (दास, शक्तिकान्त), 16 जनवरी 2021 में भी सार्वजनिक लाभ (पब्लिक गुड) के रूप में वर्णित किया गया था।

आगे की ओर देखें तो वित्तीय प्रणाली के लिए नई चुनौतियां उभरती रहेंगी। वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को अपने पूंजी के स्तर और गुणवत्ता को मजबूत करने की निरंतर आवश्यकता है, साथ ही जोखिम प्रबंधन मानकों को और भी कार्यक्षम बनाने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक अब चरणबद्ध तरीके से संशोधित बेसल III मानकों को अपनाने; अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के लिए दिशानिर्देश जारी करने; चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर); और परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए विवेकपूर्ण ढांचे जैसे मुद्दों पर काम कर रहा है। हमारा समग्र दृष्टिकोण परामर्शात्मक है। उदाहरण के लिए, ईसीएल ढांचे के संबंध में एक चर्चा पत्र जारी करने और हितधारकों की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के बाद भी, जिसकी हमने एक बाहरी कार्य समूह द्वारा जाँच कराई, अब हम ईसीएल के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा परिपत्र जारी करने का विचार कर रहे हैं। इसके पीछे सोच यह है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसके महत्व को देखते हुए इस ढांचे की कुछ विशिष्टताओं पर हितधारकों की टिप्पणियाँ प्राप्त करना है। हमारा प्रयास बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और आर्थिक संवृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि दोनों आवश्यक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। हम जलवायु जोखिमों और वित्तीय क्षेत्र पर उनके प्रभाव पर भी काम कर रहे हैं। **जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचे** के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं की निगरानी प्रक्रिया को भी एकीकृत किया गया है और सक्रिय ऑन-साइट और ऑफ-साइट पर्यवेक्षी तंत्रों के साथ इसे काफी हद तक मजबूत किया गया है। अब ध्यान प्रारंभिक पहचान और पूर्व-निवारक सुधार पर है। मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट, प्रारंभिक चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूआई), धोखाधड़ी संवेदनशीलता सूचकांक (एफवीआई), माइक्रो-डेटा विश्लेषण (एमडीए), और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीकों के उपयोग के साथ उन्नत ऑफ-साइट मूल्यांकन ढांचा अधिक विश्लेषणात्मक और दूरदर्शी है। ऑनसाइट पर्यवेक्षण अब अधिक गहराई से किया जाता है। पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ सीधे जुड़ाव में चर्चाओं और दक्ष पोर्टल माध्यम को भी शामिल किया गया है। दक्ष पोर्टल विभिन्न पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो समाधान के साथ एक सुपटेक पहल है।⁶

कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स, जिसे मई 2020 में रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित किया गया था, अब हमारे पर्यवेक्षकों को अपने कौशल को बेहतर बनाने और वित्तीय क्षेत्र में होने वाली नई और जटिल गतिविधियों के बारे में अवगत होने में मदद कर रहा है।

वित्तीय क्षेत्र वास्तव में अधिक जटिल हो गया है, जिसमें नए-नए डिजिटल उत्पाद, साझा बाजार अवसंरचना और आईटी सेवाओं के लिए साझा सेवा प्रदाता जुड़ रहे हैं। इन विकास क्रमों ने कई तरह के छोटे-बड़े जोखिम बढ़ा दिए हैं। रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं में बुनियादी साइबर सतर्कता, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण, आईटी आउटसोर्सिंग और आईटी गवर्नेंस से संबंधित विनियम जारी करके वित्तीय क्षेत्र में बढ़ती साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान सक्रियता के साथ किया है। डेटा के महत्व और उसकी भविष्य की क्षमता को समझते हुए भुवनेश्वर में एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। इसके साथ ही, एक डेटा सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र क्लाउड सुविधा स्थापित करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है।

कुल मिलाकर, भारत का वित्तीय क्षेत्र हाल ही के उथल-पुथल के दौर की शुरुआत की तुलना में अब अधिक मजबूत और समुत्थानशील है। लेकिन आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं है। विनियामक और विनियमित संस्थाओं को उभरती चुनौतियों के लिए सतर्क और भविष्य के लिए तैयार रहना होगा।

बाह्य क्षेत्र स्थिरता

भारत के बाह्य क्षेत्र ने भी हाल की अवधि में मजबूती और स्थिरता दिखाई है। चालू खाता घाटा (सीएडी) स्वीकार्य सीमा के भीतर रहा है और 2024-25 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत रहा है (वित्त वर्ष 2023-24 में 0.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022-23 में 2.0 प्रतिशत)। भारत का व्यापारिक निर्यात, जो 2023-24 में कम हो गया था, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान उबर गया। सेवा निर्यात में उछाल रहा

⁶ दक्ष उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित, कभी भी-कहीं भी भूमिका-आधारित पहुँच प्रदान करता है। इसे सभी पर्यवेक्षी कार्यों के लिए एकल इंटरफ़ेस के रूप में देखा जाता है। दक्ष में शामिल पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं में निरीक्षण योजना और निष्पादन, स्कोपिंग और संसाधन आवंटन, रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और संस्थाओं को निरीक्षण रिपोर्ट की उपलब्धता शामिल है।

और 2024-25 की पहली छमाही के दौरान उसमें 11.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2023-24 में 4.8 प्रतिशत)। सेवाओं के निर्यात में मजबूत वृद्धि, और निजी विप्रेषण में उछाल, चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने में मदद कर रहा है।

वित्त पोषण के क्षेत्र को देखें तो निवल पूंजी प्रवाह आम तौर पर सीएडी से अधिक रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार वृद्धि में योगदान दे रहा है। 31 अक्टूबर 2024 को भारत के पास 682 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है और जो पूरे विदेशी ऋण⁷ और लगभग 12 महीने के व्यापारिक आयात का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त है।⁸ अन्य प्रमुख बाह्य क्षेत्र संकेतकों, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए विदेशी ऋण, निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) और विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण के संदर्भ में भारत की स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है।

हमारी विनिमय दर नीति अच्छी तरह से निर्धारित की गई है और पिछले कई वर्षों से कार्यक्षम रही है। भारत की विनिमय दर व्यवस्था बाजार द्वारा निर्धारित है, और रिज़र्व बैंक विनिमय दर के किसी स्तर या सीमा को निर्धारित नहीं करता है। विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप विनिमय दर की व्यवस्थित गति सुनिश्चित करने और अनुचित अस्थिरता को रोकने, बाजार की अपेक्षाओं को स्थिर करने और समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि विनिमय दर किसी अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित ताकत का माप साधन भी है। यदि भारतीय रुपया (आईएनआर) 2022 और 2023 में फेड द्वारा सबसे बड़ी और सबसे कड़ी सख्ती सहित गंभीर बाह्य आघातों के बावजूद अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, तो यह टेपर टैंट्रम के दिनों से हमारे व्यापक बुनियादी ढांचे में आए बड़े बदलाव के बारे में बहुत कुछ बताता है।

यदि हम रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों के अन्य प्रमुख खंडों अर्थात् मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूति बाजार को देखें तो वास्तव में वे भी वैश्विक बाजारों के बड़े उतार-

चढ़ाव और स्पिलओवर के बावजूद स्थिर रहे हैं। भारत औसत कॉल मनी दर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) गलियारे के भीतर सीमित दायरे में रही है और नीति रेपो दर के करीब रही है। वैश्विक नीतिगत बदलाव, अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में उतार-चढ़ाव और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के बीच सख्ती के चक्र के दौरान 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल भी 6.72 से 7.61 प्रतिशत⁹ के सीमित दायरे में रहा। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजारों की समुत्थानशीलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हाल के वर्षों में कई विनियामक उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं: बेंचमार्क प्रशासकों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे की स्थापना; ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों में बाजार निर्माताओं के लिए मजबूत अभिशासन आवश्यकताएं; और गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव सुधारों के लिए मार्जिन आवश्यकताएं।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों में नवाचारों के लिए एक सक्षम पारितंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे भारतीय वित्तीय प्रणाली की दक्षता और स्थिरता बढ़ी है। चौबीसों घंटे एनईएफटी और आरटीजीएस की शुरुआत;¹⁰ एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की सफलता; और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट परियोजना (e₹) का कार्यान्वयन व्यापक वित्तीय प्रणाली को बदल रहा है। बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण को रिज़र्व बैंक की एक महत्वपूर्ण पहल - यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) से और बढ़ावा मिला है जिसे रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच), बेंगलुरु द्वारा अभिकल्पित और विकसित किया गया है। आरबीआईएच की कुछ अन्य पहलें भी विचाराधीन हैं।

समापन टिप्पणियां

रिज़र्व बैंक को प्राप्त अधिदेश कई आयामों में व्याप्त है। हमारा निरंतर प्रयास स्थिरता का समग्र दृष्टिकोण अपनाना है जिसमें मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और निरंतर विकास

⁷ जून 2024 के अंत में।

⁸ भुगतान संतुलन के आधार पर वार्षिक व्यापारिक आयात।

⁹ 16 जून 2022 तक, 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल 7.61 प्रतिशत पर पहुँच गया। 10 वर्षीय जी-सेक की प्रतिफल दर 26 सितंबर 2024 तक कम होकर न्यूनतम 6.72 प्रतिशत हो गई।

¹⁰ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) 16 दिसंबर 2019 से सप्ताहांत और छुट्टियों सहित चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया गया। रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (आरटीजीएस) 14 दिसंबर 2020 से सप्ताहांत और छुट्टियों सहित चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया गया।

शामिल है। हम इन बहु-उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई नीतिगत साधनों का प्रयोग करते हैं।

आज, भारत की आर्थिक संवृद्धि समुत्थानशील बनी हुई है; समय-समय पर होने वाले उतार-चढ़ाव के बावजूद मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है; और बाह्य क्षेत्र मजबूत है। बिना किसी

आत्मसंतुष्टि के, मैं यह कहकर समाप्त करना चाहता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था अशांति के लंबे दौर से अच्छी तरह से गुजरी है और लगातार उभरती नई चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन दिखाती है।

धन्यवाद। नमस्कार।